नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 046
दि. 18.11.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

दिल्ली के हाथ शेख हसीना की किस्मत: ढाका की अदालत ने सुनाई मौत, अब फैसला भारत की कूटनीति तय करेगी

(जीएनएस)। ढाका की सड़कों पर गूँजती गोलियों, धुएँ और चीखों के बीच जब सत्ता चरमराई, तब कोई नहीं जानता था कि यह उथल-पुथल आखिरकार दक्षिण एशिया की सबसे जटिल भू-राजनीतिक पहेली में बदल जाएगी। सैकड़ों छात्रों की मौत, हजारों घायल, हजारों गिरफ्तार, और पूरे देश में फैला असंतोष—बांग्लादेश का 2024 का छात्र आंदोलन कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया कि सेना ने खुद को तटस्थ कर लिया, संसद भंग हो गई और प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़कर देश छोड़ना पड़ा। अगस्त 2024 की उस भयावह रात में, जब बांग्लादेश का राजनीतिक क्षितिज जलती इमारतों की तरह धुआँ छोड़ रहा था, हसीना भारत की ओर निकल पड़ीं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें विशेष सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया। महीनों से उनका पता गुप्त रखा गया है, लेकिन उन्हें भारत की भूमि पर सुरक्षित माना जाता है। ढाका की जमीन पर meanwhile, एक मुकदमा चल रहा था, जिसकी गंभीरता पूरे क्षेत्र की राजनीति को अपनी गिरफ्त में लेने वाली थी। बांग्लादेश की International Crimes Tribunal-1 ने 17 नवंबर को हसीना के खिलाफ तीन बड़े अभियोगों का हवाला देते हुए उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। कहा गया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले की अनुमति दी, शहरी आबादी को लक्षित करने के आदेश दिए और सुरक्षा बलों का उपयोग युद्ध जैसे अभियान में किया। अदालत ने उन्हें "क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी" का दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग भी अदालत में पेश की, जिसमें एक कथित आवाज़ को यह कहते सुना गया—"मेरे खिलाफ दर्ज केस मुझे मारने का लाइसेंस देते हैं।" इस रिकॉर्डिंग को अदालत ने निर्णायक माना और फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सेना और पुलिस के अत्यधिक दमन का स्पष्ट सबूत है।

लेकिन भारत में छिपी शेख हसीना ने इस फैसले को राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने इसे 'कंगारू कोर्ट' कहा और दावा किया कि अंतरिम प्रशासन चुनावों से पहले उन्हें और उनकी पार्टी अवामी लीग को राजनीति से बाहर करना चाहता है। हसीना का कहना है कि यह न्याय नहीं, बल्कि बदला है—और वह इस अदालत को मान्यता ही नहीं देतीं।

अब सवाल यह है कि ढाका का यह फैसला भारत में क्या असर छोड़ता है? क्या भारत विदेशी अदालत की मौत की सज़ा को लागू करता है? भारतीय कानून कहता है कि किसी विदेशी कोर्ट का फैसला भारत में तब तक लागू नहीं होता, जब तक भारतीय अदालत उसे खुद स्वीकार न करे। इसलिए भारत में मौजूद शेख हसीना पर ICT-1 की मृत्यु दंड का कोई सीधा प्रभाव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र भी इस फैसले को लागू नहीं करा सकता, क्योंकि ICT-1 एक घरेलू अदालत है, किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की तरह अधिकार-युक्त संस्था नहीं।

दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंप सकता है? भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि ज़रूर है, लेकिन भारत के पास कानूनी ढालें हैं जो उसे प्रत्यर्पण रोकने की पूर्ण अनुमति देती हैं। भारत का प्रत्यर्पण कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक साजिश, प्रतिशोध या निष्पक्ष ट्रायल की अनुपस्थिति में फँसाया गया हो, या उसे मौत की सज़ा का खतरा हो, तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में भारत कानूनी रूप से यह कह सकता है कि हसीना को सौंपना संभव नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हसीना की जान अब अदालत नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति के फैसलों पर टिकी है।

यदि भारत उन्हें सौंप देता है, तो बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाएँ भड़क सकती हैं। अवामी लीग समर्थकों का गुस्सा भारत के खिलाफ केंद्रित हो सकता है और भारत पर "शासन बदलने" या "राजनीतिक दखल" का आरोप लगाया जा सकता है। वहीं दक्षिण एशिया में भारत की छवि को भी झटका लग सकता है। इसके उलट, अगर भारत उन्हें न लौटाए, तो भी मुश्किलें कम नहीं होंगी। सीमा पार व्यापार और सुरक्षा सहयोग प्रभावित होने का खतरा है। बांग्लादेश का झुकाव चीन की ओर बढ़ सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है।

इसीलिए, यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के बंद कमरों में और भी गहरे स्तर पर समझा जा रहा है। विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि भारत तीन मार्गों में से कोई भी चुन सकता है: या तो चुपचाप शरण जारी रखे और मामले को लंबित रखे; या फिर साफ तौर पर कहे कि राजनीतिक प्रतिशोध और मौत की सज़ा को देखते हुए प्रत्यर्पण संभव नहीं है; या फिर बांग्लादेश के सामने शर्त रख दे कि यदि मौत की सज़ा हटाई जाए और अंतरराष्ट्रीय निगरानी में निष्पक्ष मुकदमा हो, तभी प्रत्यर्पण पर विचार किया जा सकता है।

हिमाचल: पंचायत और नगर निकायों के पुनर्गठन पर रोक, चुनाव प्रक्रिया को प्राथमिकता

(जीएनएस)। शिमलाः हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की पंचायतों और नगर निकायों की सीमाओं, संरचना और वर्गीकरण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम स्थानीय निकायों के समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, 2020 के प्रावधानों को लागू करते हुए यह निर्णय लिया।

निर्वाचन आयुक्त का आदेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243E(1) और 243U(1) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावी प्रक्रिया उनके पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले शुरू करना अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया कि अब पंचायतों के पुनर्गठन के लिए केवल 75 दिन और शहरी निकायों के लिए लगभग 60 दिन शेष हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

'फ्रीज' हुई सीमाएँ, पुनर्गठन पर रोक

निर्वाचन आयोग पहले भी साफ कर चुका

है कि एक बार परिसीमन अधिसूचना अंतिम हो जाने के बाद किसी भी निकाय की सीमाएँ स्वतः 'फ्रीज' मानी जाएँगी। इसी आधार पर आयोग ने आदेश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य की किसी भी पंचायत या नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी तरह का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा।

सरकार की पुनर्गठन प्रक्रिया पर विराम

प्रदेश सरकार ने हाल ही में पुनर्गठन प्रक्रिया प्रारंभ की थी और पंचायती राज विभाग ने 1 नवंबर को सभी उपायुक्तों को 15 दिन के भीतर अपने प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। आयोग के आदेश के बाद यह प्रक्रिया अब रोक दी गई है।

अप्रैल तक समाप्त हो रहा कार्यकाल

हिमाचल प्रदेश में कई स्थानीय निकायों का कार्यकाल 2026 की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक समाप्त होने वाला है। पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी, 50 नगर निकायों का 18 जनवरी और धर्मशाला, पालमपुर, मंडी व सोलन नगर निगमों का 13 अप्रैल को पूरा होगा। वहीं, कुछ नगर पंचायतों जैसे अंब, चिड़गांव, कंडाघाट, नेरवा और निरमण्ड का कार्यकाल 16 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा।

परिसीमन और मतदाता सूचियों की स्थिति

राज्य में 3,577 ग्राम पंचायतों, 90 पंचायत समितियों, 11 जिला परिषदों और 71 नगर निकायों की परिसीमन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इनमें से अधिकांश निकायों की मतदाता सूचियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जबकि शेष सूचियाँ 1 तथा 7 दिसंबर 2025 को जारी की जाएँगी।

स्थानीय लोकतंत्र सुरक्षित, चुनाव समय पर होंगे

इस आदेश के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित न हो और चुनाव समय पर सम्पन्न हों। आयोग का यह कदम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारु संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत–फ्रांस हवाई अभ्यास 'गरुड़' में सुखोई 30 और राफेल ने दिखाया सामरिक दम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय हवाई सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित हवाई अभ्यास 'गरुड़' का नवीनतम संस्करण फ्रांस के मोंट-डी-मार्सन एयर बेस पर शुरू हो गया है। इस अभ्यास के पहले चरण में भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 एमकेआई और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने समन्वित मिशनों के तहत उड़ान भरकर संयुक्त संचालन और युद्ध स्थितियों में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। भारतीय वायु सेना का दल 13 नवंबर को फ्रांस पहुंचा था, और इस अभ्यास में सुखोई-30 एमकेआई विमान के अलावा अन्य तकनीकी और सामरिक संसाधन भी शामिल हैं। दोनों सेनाएँ इस अभ्यास के दौरान कृत्रिम युद्ध वातावरण में प्रशिक्षण लेंगी, जिसमें एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक, मिशन प्लानिंग और संचार प्रणाली के समन्वित प्रयोग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता साझा की जाएगी।

सहयोग और अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि

'गरुड़' अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाना और सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है। फ्रांसीसी वायु सेना इस बार चार राफेल लड़ाकू विमान, एक ए-330 मल्टी-रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट और लगभग 220 सैन्य कर्मियों के साथ इस अभ्यास में शामिल हो रही है। दोनों देशों के पायलट आपसी रणनीतिक दृष्टिकोण और संचालन तकनीकों से परिचित होंगे, जिससे भविष्य में संयुक्त अभियानों में सहयोग और भी प्रभावी होगा। 'गरुड़' हर दो वर्ष में आयोजित किया जाता है और अब यह आठवें संस्करण में है। पहले, तीसरे और पांचवें संस्करण क्रमशः 2003 (ग्वालियर), 2006 (कलाईकुंडा) और 2014 (जोधपुर) में भारत में आयोजित हुए। जबकि दूसरे, चौथे और छठे संस्करण 2005, 2010 और 2019 में फ्रांस में संपन्न हुए। पिछला अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, जिसमें दोनों देशों के वायु सेना प्रमुखों ने लड़ाकू विमानों में उड़ान भरकर संयुक्त संचालन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। 'गरुड़' अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों के पायलट जमीनी और हवाई अभियानों में एक-दूसरे की तकनीक, रणनीति और संचालन पद्धतियों को समझेंगे। इससे न केवल दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग मजबूत होगा, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को भी नई दिशा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभ्यास भारत-फ्रांस के सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और गहन बनाने के साथ-साथ क्षेत्रीय सामरिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। अभ्यास 27 नवंबर तक जारी रहेगा और इसमें भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच तकनीकी, रणनीतिक और संचालनात्मक अनुभवों का व्यापक आदान-प्रदान होगा, जिससे दोनों देशों की साझेदारी और मजबूती की ओर एक बड़ा कदम उठाने में मदद मिलेगी।

"सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: टाइगर संरक्षण अब राष्ट्रीय दायित्व, मानव–वन्यजीव संघर्ष में हर मौत पर 10 लाख मुआवजा अनिवार्य"

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जो फैसला सुनाया, उसने देश में वन्यजीव संरक्षण के पूरे ढाँचे को एक नई दिशा दे दी है। अदालत ने पहली बार यह स्पष्ट और कड़ा संकेत दिया कि बाघों की सुरक्षा, जंगलों की मर्यादा और मनुष्यों के जीवन की रक्षा अब एक साथ जुड़े हुए राष्ट्रीय दायित्व हैं। वर्षों से जंगलों की सीमाओं के आसपास बसे ग्रामीण मानव–वन्यजीव संघर्ष की कीमत जान देकर चुका रहे हैं, लेकिन अब अदालत के आदेश ने इस दर्दनाक वास्तविकता को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखकर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इतिहास में कभी-कभार ही ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाघ संरक्षण पर इतने व्यापक और दूरगामी निर्देश एक साथ जारी किए हों। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने साफ कहा कि यदि किसी राज्य में बाघ, तेंदुआ या अन्य वन्य जीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो सरकार को कम से कम दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि देना अनिवार्य होगा। यह मुआवजा देना किसी सद्भावना या दया का निर्णय नहीं बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी होगी, जिसे टाला नहीं जा सकता।

उत्तर प्रदेश ने पहले ही मानव–वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानकर इस दिशा में कदम उठाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यही मॉडल पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को छह महीने के भीतर एक मॉडल

गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। उसके बाद राज्यों को भी अगले छह महीनों में इसे लागू करना होगा, ताकि राहत प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी बन सके।

फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोर और बफर जोन की परिभाषा, गतिविधियों की अनुमतियों और बाघों के प्रवास क्षेत्रों में पर्यटन और निर्माण पर पूरी तरह पुनर्विचार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कोर क्षेत्र में कभी भी किसी तरह की टाइगर सफारी की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये इलाके प्रकृति के मंदिर हैं, जहां मानव उपस्थिति न्यूनतम होनी चाहिए। सफारी सिर्फ बफर जोन की गैर–वन या बंजर भूमि पर ही स्थापित की जा सकेगी, वह भी तभी जब वह बाघों के किसी भी प्राकृतिक गलियारे में बाधा न डालती हो। अदालत के शब्दों में, यदि देश को पर्यटन बढ़ाना है तो वह केवल 'इको–टूरिज्म' की भावना के साथ बढ़े, व्यापारिक और शोरगुल वाले पर्यटन के साथ नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जंगलों में काम करने वाले वनकर्मियों को, जो अपने परिवारों से दूर कठोर परिस्थितियों में रहते हैं, विशेष सुविधाएँ और सुरक्षा दी जानी चाहिए।

फैसले ने यह भी घोषित किया कि सभी टाइगर रिजर्व को तीन महीने के भीतर 'साइलेंस ज़ोन' घोषित किया जाए। इसका अर्थ यह है कि बाघ अभयारण्यों में किसी भी प्रकार का अनावश्यक शोर वर्जित होगा। आपात वाहनों को छोड़कर रात के समय वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। रात का पर्यटन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम बाघों के प्राकृतिक जीवन चक्र, शिकार और आराम को बाधित होने से बचाने के लिए अनिवार्य माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की उन सभी सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है जिन्हें टाइगर रिजर्व के बफर इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची के रूप में निर्धारित किया गया था। इन गतिविधियों में वाणिज्यिक खनन, आरा मिलें, प्रदूषणकारी उद्योग, बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं, खतरनाक रसायन उत्पादन और कम–ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों की आवाजाही शामिल हैं। अदालत ने इन सबको प्रतिबंधित कर बाघ संरक्षण को केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक समन्वित प्रशासनिक दायित्व की तरह परिभाषित किया है। उधर, उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर हुए बड़े पैमाने के अवैध निर्माण, रिसॉर्ट्स और पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद कड़ा रहा। अदालत ने राज्य सरकार को तीन महीने की समयसीमा देते हुए निर्देश दिया है कि इन सभी अवैध संरचनाओं को तत्काल ध्वस्त किया जाए और कटे हुए पेड़ों की पूर्ण पर्यावरणीय भरपाई की जाए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जंगलों में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और निजी लाभ की कोई जगह नहीं हो सकती। पुनर्स्थापना योजना की निगरानी सीईसी करेगा, ताकि सुधार कागजों में नहीं, जमीन पर दिखे।

इस फैसले के बाद पूरा ध्यान अब राज्यों पर है—क्या वे राहत प्रणाली को सरल बनाएंगे? क्या ग्रामीणों को मुआवजा पाने के लिए महीनों तक कागजों में नहीं भटकना पड़ेगा? क्या जंगलों की सीमाओं के बाहर तेजी से बस्तियां बढ़ाने वाले राजस्व और शहरी विभाग अब वन संरक्षण के साथ तालमेल बैठाना सीखेंगे?

इन तमाम सवालों के बीच एक बात स्पष्ट है—भारत में बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं, एक राष्ट्रीय पहचान हैं। मनुष्य और प्रकृति के इस संघर्ष में अदालत ने पहली बार मानव की त्रासदी और पशु की सुरक्षा को एक ही तराजू पर रखकर न्याय किया है। अब यह जिम्मेदारी राज्यों की है कि वे इस फैसले को जीवन और जंगल दोनों की सुरक्षा का वास्तविक आधार बनाएं।

संपादकीय

एडिक्शन छुड़ाने को केरल में खुले

कोरोना संकट ने जहां ऑनलाइन शिक्षा के जरिये छात्रों को पढ़ाई का कारगर विकल्प दिया, तो वहीं छात्र-छात्राओं को डिजिटल एडिक्शन का शिकार भी बना दिया। मां-बाप को लगता था कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में व्यस्त हैं, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चे ऑनलाइन गेम की लत के शिकार बने हुए थे। हाल के दिनों में पढ़ाई के माध्यमों और जीवनशैली में बदलाव के चलते बच्चे तेजी से डिजिटल लत के शिकार होने लगे हैं। मगर उन्हें ये सब सामान्य लगता था। यदि मां-बाप उन्हें इससे रोकते हैं, तो टोका-टाकी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। उनका व्यवहार आक्रामक भी होने लगता है। कहीं-कहीं तो मां-बाप की सख्ती के बाद छात्रों के आत्महत्या करने के मामले भी सामने आए। केरल में सिर्फ पलक्कड़ में चार साल के भीतर 41 बच्चों द्वारा आत्महत्या करने के दुखद समाचार आए, जिसने प्रशासन और अभिभावकों की नींद उड़ा दी। डिजिटल लत से बच्चों को मुक्त करने के लिए केरल सरकार ने नई पहल की। पलक्कड़ में छह डि-एडिक्शन सेंटर शुरू किए हैं, जिनमें बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। यहां मौजूद साइकोलॉजिस्ट लत के शिकार बच्चों का इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट करते हैं, जिससे पता लगाया जाता है कि लत का स्तर क्या है। जिसके आधार पर उनकी काउंसलिंग की जाती है। इसके लिए जहां कुछ एक्सरसाइज करायी जाती हैं, वहीं दूसरी रचनात्मक गतिविधियों से इसे छुड़ाने की कोशिश की जाती है। इस दौरान एक-एक घंटे के दस-पंद्रह सेशन कराये जाते हैं। सुखद है कि चार-पांच सेशन के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

दरअसल, डिजिटल लत के शिकार बच्चों को यह बताना कठिन होता है कि वे डिजिटल लत के शिकार हैं। वे मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे कुछ असामान्य कर रहे हैं। उनके लिये यह व्यवहार सामान्य घटनाक्रम है। लेकिन डि-एडिक्शन सेंटर में काउंसलिंग और कुछ सेशन के बाद उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। दरअसल, सोशल मीडिया का जाल हमारे समाज का ग्रास इतनी तेजी से कर रहा है, बच्चों को लगता ही नहीं कि वे कुछ असामान्य कर रहे हैं। जिसके चलते किशोर, इससे रोकने पर आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं। कुछ मामलों में वे अवसादग्रस्त होने लगते हैं या फिर उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। यह सुखद है कि पलक्कड़ में पिछले दो साल में साढ़े बारह सौ बच्चों को डिजिटल लत से मुक्ति दिलायी गई है। बच्चे मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। दरअसल, आज जरूरत इस बात की है कि स्कूलों में शिक्षक व अभिभावक पढ़ाई और इंटरनेट के प्रयोग में संतुलन बैठाने का प्रयास करें। सही मायने में यह संकट सिर्फ केरल के किसी एक जिले का ही नहीं है, यह संकट पूरे देश का है। जिसको लेकर केंद्र सरकार को यथाशीघ्र नीति बनाने और डि-एडिक्शन सेंटर खोलने की जरूरत है। इस दिशा में केंद्र व राज्यों के सहयोग से सकारात्मक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इस कार्य में स्वयंसेवी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

तिरस्कार से मतदाता ने दिया विपक्ष को संदेश

> “जैसा कि बिहार ने दिखाया है और चुनाव दर चुनाव स्पष्ट रहा है, भाजपा की जीत की भूख पर कभी कोई संदेह नहीं रहा। शायद विपक्ष को उस किताब से सीख लेने के बारे में विचार करना चाहिए, जिसे उसका राजनीतिक दुश्मन पिछले कुछ समय से पढ़ रहा है।

बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत, तेजस्वी यादव के राजद को सजा और कांग्रेस पार्टी का सफाया निश्चित तौर पर तय था। एक और बात स्पष्ट है। राहुल गांधी को कोलंबिया जाकर बस जाना चाहिए या किसी अन्य दक्षिण अमेरिकी देश में, जहां वे बिहार चुनाव प्रचार के बीच सफेद कुर्ता-पायजामा और काली बंडी जैकेट में फबकर घूमते दिखाई दिए थे। हिंदी में - और पंजाबी में भी- एक शब्द है बिहारी, इसका अभिप्राय उपेक्षित से कुछ अधिक और हेय से कुछ कम लिया जाता है, गत सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस के खिलाफ वोट देते वक्त यह मतदाताओं के मन में जरूर रहा होगा।

तिरस्कार। हिकारत। हमें हल्के में मत लीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको आपकी जगह दिखा देंगे, एक ऐसी पार्टी को वोट देकर, जिसके बारे में हमने शायद सोचा हो या नहीं भी।

बिहार में, मतदाता कांग्रेस -यानी राहुल गांधी- के प्रति इतनी गुस्से से भर गए कि उन्होंने इस सबसे पुरानी पार्टी को छह सीटों तक सीमित कर दिया। डेढ़ साल पहले हुए लोकसभा चुनावों के बाद से यह कांग्रेस की लगातार चौथी हार है - हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद। भारतीय राजनीति की त्रासदी यह है कि राहुल को जवाबदेह होने, दक्षिण अमेरिका न जाने या दीवार पर लिखी इबारत को समझना मंजूर नहीं है -यह कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए और खुद अपनी पार्टी में लोकतंत्र की उस हवा को बहने देना चाहिए, जिसके बारे में बात करना उन्हें बहुत पसंद है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर, दोनों सूबों में लोगों ने कुछ गढ़ हिला दिए हैं - और सत्तारूढ़ आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट चेतावनी दे दी है। तरनतारन और बडगाम, दोनों जगहों पर

मतदाताओं ने कहा है कि हमें हल्के में मत लीजिए। तरनतारन में, जो गर्म राजनीति का केंद्र रहा है, नाराज़ पंजाबी मतदाता ने अपने कुछ संदेश भेजे हैं। पहला,उन्होंने राज्य में विधानसभा चुनावों से 15 महीने पहले सत्तारूढ़ 'आप' को चेतावनी संकेत दे दिया है। दूसरा, 'आप' उम्मीदवार जीत तो गया, लेकिन अकाली दल के प्रत्याशी ने उसे करारी टक्कर दी है - भले ही इस पर एक राय न हो कि पंजाब की राजनीति में क्या इसे अकाली दल की वापसी माने या नहीं, क्योंकि पार्टी ने 2020 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून लागू करने पर, एनडीए से नाता तोड़ने के बाद से, अपना जादू खो दिया है, 2022 के विधानसभा चुनावों में अकाली दल ने केवल तीन सीटें जीतीं थीं, तो 2024 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई और तब से गुटबाजी में घिरी हुई है।

तीसरा, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अकाली उम्मीदवार सुखविंदर कौर ने अलगाववाद परस्त राजनीतिक संगठन 'वारिस पंजाब दे' (डब्ल्यूपीडी) द्वारा समर्थित उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया – उसका प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा। सनद रहे, डेढ़ साल पहले ही खालिस्तान समर्थक डब्ल्यूपीडी ने लोकसभा में दो सीटें जीती थीं - एक पर इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा विजयी रहा, जबकि दूसरी सीट का विजेता विद्रोह के प्रयास के लिए जेल में है। इसलिए अगर तरनतारन अब मध्यमार्ग की लीक पर लौट रहा है, तो अकाली दल निश्चित रूप से दोहरी श्लाघा और पीठ थपथपाने का हकदार है।

चौथा, तरनतारन ने कांग्रेस के साथ घोर अपमानजनक भरा बर्ताव किया है – जिसके ओहदेदारों को यकीन है कि वे उस राजगद्दी के नैसर्गिक हकदार हैं, जब पंजाब के लोग बहुत जल्द 'आप' को विदा कर देंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई वहीं भाजपा पांचवें स्थान पर रही, इस तसल्ली के साथ कि हमने भी दौड़ में हिस्सा लिया।

फिर एक संदेश बडगाम से आया है, जहां से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले सितंबर में गांदेरबल निर्वाचन क्षेत्र के साथ जीत हासिल की थी – उन्होंने बडगाम खाली किया था, जिसकी वजह से वहां उपचुनाव करवाया गया। स्पष्टतः सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अब्दुल्ला को सजा इसलिए मिली है क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की लोगों की उम्मीदों को वे पूरा नहीं कर पाए हैं - भले ही यह करना उनके हाथ में न होकर केंद्र सरकार के हाथ में है। अब्दुल्ला को इस तथ्य की कीमत चुकानी पड़ी है कि वास्तव में वह केवल अधूरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं।

मतदाताओं द्वारा दिखाया यह निष्ठुर रवैया प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा और नीतीश कुमार की जदयू को मिली ज़बरदस्त तालियों के बिल्कुल उलट है। कई विश्लेषकों ने एनडीए की अभूतपूर्व जीत का श्रेय न सिर्फ़ महिलाओं को, बल्कि सभी सब मतदाताओं को बड़े पैमाने पर किए नकद हस्तांतरण को दिया है - जन सुराज पार्टी नेता पवन के वर्मा ने द ट्रिब्यून को बताया कि भाजपा शासित केंद्र ने आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले ही 30,000 करोड़ रुपये लोगों के खाते में डाले, जो एक बेहद गरीब राज्य के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। शायद बिहार का मतदाता यह सोचकर डर गया था कि राजद के साथ 'जंगल राज' वापस आ जाएगा - निश्चित रूप से, लालू के बेटे में सामाजिक न्याय सुधार के लिए वो आग नहीं है जो लालू यादव में थी, भले ही उनमें और कमियां रही हों। और जहां ये तमाम कारण पूरी तरह से प्रासंगिक हैं, कोई भी पूरी तरह से यह नहीं समझा पा रहा कि बिहार इतनी आसानी से भगवा क्यों हो गया और उसने विपक्ष के साथ इतनी नफरत या उपेक्षा भरा बर्ताव क्यों किया।

आखिरी बात यह है कि विपक्ष ने असली लड़ाई लड़नी ही नहीं चाही। राहुल गांधी बीच संग्राम बिहार छोड़ कर निकल गए (दक्षिण अमेरिका के लिए), तेजस्वी यादव ने जल्दबाज़ी में वह वादे कर दिए जिन्हें वे पूरा कर ही नहीं सकते थे (हर परिवार में एक सरकारी नौकरी) और जन सुराज के प्रशांत किशोर ने गुस्से और अहंकार खुद पर हावी होने दिया ('अगर नीतीश कुमार को 25 से ज़्यादा सीटें मिलीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा'), यह बात उनकी सोची-समझी रणनीति के आड़े आ गई। महागठबंधन इसलिए नहीं जीत पाया क्योंकि वह असल में लड़ाई में कभी था ही नहीं।

ऐसे में जब आपके सामने एक तरफ महाशक्ति हो और दूसरी ओर एक कमज़ोर गठबंधन, जिसे खुद पर भी भरोसा नहीं है तब बतौर मतदाता आप क्या करेंगे? गिनाने को भाजपा के साथ भी कई कमियां हैं–तथ्यों में अग्रणी एक यह कि चुनाव को अपनी तरफ़ मोड़ने के लिए केंद्र सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल करने में भाजपा ने कोई संकोच नहीं किया, उदाहरणार्थ, महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण।

जैसा कि बिहार ने दिखाया है और चुनाव दर चुनाव स्पष्ट रहा है, भाजपा की जीत की भूख पर कभी कोई संदेह नहीं रहा। शायद विपक्ष को उस किताब से सीख लेने के बारे में विचार करना चाहिए, जिसे उसका राजनीतिक दुश्मन पिछले कुछ समय से पढ़ रहा है।

प्रेरणा

चोरी हुए जूतों का सत्य

शहर की गलियों में सुबह का उजाला फैल चुका था। मंदिर के बाहर पूजा का समय नज़दीक आ रहा था और भक्तों का आना-जाना बढ़ने लगा था। भीड़ में एक धनी व्यक्ति भी धीरे-धीरे चलता हुआ आया। उसके कपड़ों से लेकर उसके कदमों तक में सम्पन्नता झलक रही थी, और उसके पैरों में वह जूते थे जिनकी चमक किसी आईने की तरह रोशनी को लौटा रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने जूते उतारे, पर जैसे ही उन्हें हाथ में लिया, एक हल्की-सी चिंता उसके चेहरे पर तैर गई—क्या ये इतने कीमती जूते यहां सुरक्षित रह पाएंगे?

उसी समय उसकी नजर मंदिर के फाटक के पास बैठे एक भिखारी पर पड़ी। भिखारी की आंखों में भूख की खालीपन थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं, बल्कि एक अजीब-सी विनम्रता थी। धनी व्यक्ति उस पर कुछ क्षणों तक नजरें गड़ाए रहा, जैसे अपने भीतर किसी बात का फैसला कर रहा हो। फिर वह आगे बढ़ा और बोला, "भाई, मेरे जूतों का ज़रा ध्यान रखना। मैं पूजा करके अभी लौटता हूं।"

भिखारी ने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। एक क्षण के लिए उसका चेहरा जैसे खिल उठा—शायद पहली बार किसी ने उसे वस्तु की देखभाल जैसे विश्वास से भरा काम सौंपा था। धनी व्यक्ति एक संतोषभरी सांस लेकर मंदिर के भीतर चला गया।

मंदिर के अंदर दीपकों की लौ शांत थी, लेकिन उसी शांति में कई सवाल उठते हैं। वह भी उसी शांति के बीच खड़ा होकर सोचने लगा—किस दुनिया में रह रहे हैं हम? किसी के पैरों में हजारों के जूते, और किसी

के पास पैरों में पहनने को चप्पल तक नहीं। किसी के घरों में इतनी समृद्धि कि चीजें अलमारियों में जगह न पाएं, और किसी के पास रात भर ओट लेने की जगह भी न हो। उसके मन में भिखारी का चेहरा घूमने लगा। उसे लगा कि बाहर जाकर वह उसे सौ रुपये देगा। शायद आज उसकी भूख मिटे, शायद वह एक दिन चैन से सो पाए।

पूजा खत्म हुई। वह बाहर आया—पर सामने का दृश्य बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वहां न जूते थे, न भिखारी। वह कुछ क्षणों के लिए वहीं ठिठक गया। जैसे किसी ने उसके मन में उठे भावों को अचानक रोक दिया हो। उसने इधर-उधर देखा, भीड़ में भिखारी जैसा कोई नहीं था। समय गुजरता गया, पर न जूते लौटे, न वह आदमी। कुछ देर इंतजार के बाद उसने मान लिया कि अब कुछ भी वापस नहीं आने वाला।

वह नंगे पैर सड़क पर चलने लगा। शहर का रास्ता कठोर था, और उसकी गर्मी उसके पैरों में उतर रही थी। पर भीतर कहीं एक अजीब-सी खामोशी फैलती जा रही थी। वह सोच रहा था—क्या गरीबी इंसान को चोरी पर मजबूर कर देती है? या आदतें इंसान का चरित्र बनाती हैं? भगवान इंसान की नियति कैसे लिखते हैं?

चलते-चलते वह फुटपाथ के पास पहुंचा, जहां एक आदमी पुराने जूते-चप्पल बेच रहा था। ढेर सारी घिसी-पिटी चप्पलों के बीच उसकी नजर अपने महंगे, चमकदार जूतों पर जा अटकी। दिल एक धड़कन के लिए ठहर गया, पर उसने खुद को संयत किया और पूछा, "ये जूते कहां से आए?"

विक्रेता ने सहज स्वर में कहा, "एक भिखारी अभी थोड़ी देर पहले बेच गया। बोला, बहुत ज़रूरत है, इसलिए सौ रुपये में दे दिए।"

धनी व्यक्ति ने सुना, पर उसके भीतर कोई तूफान नहीं उठा। न गुस्सा, न हैरानी। केवल एक गहरी, शांत मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। वही सौ रुपये—जिसे वह खुद देने का सोच रहा था। भिखारी ने वही लिया, पर अपने तरीके से, अपने समय पर। एक पल को उसने सोचा, शायद यह घटना चोरी नहीं थी; यह जीवन का एक सत्य था, जो उसे समझना था।

वह बिना जूते खरीदे आगे बढ़ गया। नंगे पैर, लेकिन भीतर कोई पीड़ा नहीं। उसने महसूस किया कि आज भगवान ने उसे किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि इस छोटी-सी घटना से उत्तर दिए हैं। वह समझ गया कि भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों का प्रतिबिंब है। हर इंसान वैसा ही पाता है, जैसा वह किसी और को देता है।

धूप अब और तेज थी, पर उसके कदम हल्के होते जा रहे थे। आज उसने सीख लिया था—

भाग्य बाहर नहीं खोजा जाता,
भाग्य हमारे ही अंदर पैदा होता है,
और उसे आकार देते हैं हमारे कर्म।

डांवाडोल होती अमेरिकी अर्थव्यवस्था, डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी से कमजोर हो रही

अमेरिका प्रथम की मुहिम के साथ चलने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हर निर्णय चाहे वह अंतरराष्ट्रीय समझौता हो, व्यापार नीति हो या सुरक्षा निर्णय दूसरों पर थोपने की नीति पर केंद्रित रहता है। वैश्वीकरण की गति को धीमा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। ट्रंप प्रशासन उन अनेक बहुपक्षीय संस्थाओं की या तो फंडिंग कम कर रहा है या उनसे बाहर निकलने की धमकियां देकर उनकी भूमिका को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, जो कथित तौर पर अमेरिका के हित में कार्य नहीं कर रही हैं। उनकी इस नीति का असर केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी इसका व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। व्यापार युद्ध ने न केवल विदेशी व्यापार को झटका दिया है, बल्कि अमेरिका के घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि को भी बढ़ावा दिया है।

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के प्रतिरोध में अन्य देशों द्वारा लगाए जाने वाले जवाबी टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है। अमेरिका में न सिर्फ रोजमर्रा की वस्तुएं, बल्कि इलेक्ट्रानिक उपकरण, खिलौने, कपड़े, मशीनें आदि के महंगे होने से अमेरिका में मार्च 2025 के बाद से आयातित सामान की कीमतें लगभग चार प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि घरेलू सामान की कीमतें लगभग दो प्रतिशत बढ़ गई हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ट्रंप ने 200 से अधिक वस्तुओं पर से टैरिफ कम करने का फैसला किया है।

अमेरिका में उद्योगों के लिए कच्चा माल महंगा होने से बढ़ती उत्पादन लागत से नौकरियां ही नहीं घट रही हैं, बल्कि किसानों की आय पर भी गहरा असर पड़ रहा है। चीन, कनाडा और यूरोपीय देशों द्वारा प्रतिशोध में लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिकी सोया और मक्का जैसी कृषि वस्तुओं की मांग घटी है, जिससे किसानों की आय में गिरावट आने से सरकार को अरबों डालर की सब्सिडी देनी पड़ रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्परिणाम अब स्पष्ट दिखने लगे हैं।

येल विश्वविद्यालय के बजट अध्ययन केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ और विदेशी प्रतिकारात्मक करों के कारण 2025 में अमेरिका की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगभग 0.9 प्रतिशत अंक कम हो रही है। टैरिफ नीतियों के कारण एक आम अमेरिकी परिवार को औसतन 3,800 डालर तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पेन-वार्टन बजट माडल का विश्लेषण बताता है कि ट्रंप की व्यापारिक नीतियों के कारण अमेरिका की जीडीपी दीर्घकाल में लगभग छह प्रतिशत तक घट सकती है और मजदूरी में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

ओईसीडी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि यदि टैरिफ और एकतरफा व्यापार नीतियां जारी रहीं तो 2026 तक अमेरिका की जीडीपी वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत तक गिर सकती है। यह गिरावट न केवल अमेरिका, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का कारण होगी, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार का मुख्य इंजन है। आम अमेरिकी इस नीतिगत बदलाव की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। उच्च मूल्य, घटती आय और रोजगार के अवसरों में कमी ने अमेरिकी सपने की धारणा को कमजोर किया है।

ट्रंप की मनमानी नीतियों का अमेरिका में विरोध भी शुरू हो चुका है। एक हालिया सर्वेक्षण में लगभग 55 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि ट्रंप अब एक खतरनाक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में अमेरिका का लोकतांत्रिक ढांचा पहले की अपेक्षा अधिक विभाजित हो गया है। "हैंड्स आफ" और "नो किंग" जैसे आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी जनता अब अधिक हस्तक्षेप और केंद्रीकृत शक्ति के विरोध में एकजुट हो रही है।

डगमगाती अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ट्रंप की राष्ट्रवादी नीतियां और अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हैं। "अमेरिका प्रथम" के उनके नारे ने जहां कुछ समय के लिए घरेलू उद्योगों को सहारा दिया, वहीं वैश्विक व्यापारिक साझेदारियों से दूरी ने अमेरिकी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अंतरराष्ट्रीय निवेश घटा है, निर्यात पर दबाव बढ़ा है और डालर की अस्थिरता से आयात महंगा हुआ है। इस बीच बेरोजगारी में वृद्धि और उपभोक्ता कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को कमजोर कर दिया है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप की नीतियों से आर्थिक असमानता बढ़ी है, जबकि श्रमिक वर्ग को उनके वादों का कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों ने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को सीमित कर दिया है, जिससे नई नौकरियां सृजित होने के बजाय उद्योगों में छंटनी बढ़ी है। वित्तीय अस्थिरता और महंगाई ने अमेरिकी जनता की चिंता को गहरा किया है।

ट्रंप का राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण ही नहीं, बल्कि आर्थिक असंतुलन का कारण भी बनता जा रहा है। अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए अपनाई गई नीतियां दीर्घकाल में अमेरिका की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक विश्वसनीयता, दोनों को कमजोर कर रही हैं। अगर यही रुझान जारी रहा तो "अमेरिका प्रथम" की नीति स्वयं अमेरिका की आर्थिक नींव को हिला सकती है।

अभियान

गीता के ज्ञान से जीवन सत्य की खोज: कर्म, योग और आत्मा का संदेश

गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक जीवन-दर्शन है। यह वह अमूल्य खजाना है, जिसने हजारों वर्षों तक मानव मन और जीवन को दिशा दी है और आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही जीवंत है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन और भगवान श्रीकृष्ण के बीच हुआ संवाद केवल युद्ध की रणनीति या राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन के गहन सत्य, कर्तव्य, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का समागम था। अर्जुन का मोहपाश, उसकी शंका और उसका भय इतना प्रबल था कि वह अपने ही बंधुओं के सामने अपने हाथ से धनुष उठाने में असमर्थ हो गया। उसने कहा, "हे वासुदेव! मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मुख सूखा जा रहा है, मन भ्रमित है, और मुझे खड़ा होना भी कठिन लग रहा है। मैं अपने ही बंधुओं को मारना नहीं चाहता, चाहे पृथ्वी का राज्य हो या तीनों लोकों का अधिकार।"

यहीं से गीता का संदेश जन्म लेता है। इसी क्षण भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और योग के अद्भुत सूत्रों से अवगत कराया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन में कर्तव्य का पालन और सच्चा कर्म ही मनुष्य को मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कर्म का फल किसी की इच्छा, मोह या भय से प्रभावित नहीं होता, और यही कर्म ही मानव के भाग्य की दिशा तय करता है।

शांति और युद्ध के बीच का यह संघर्ष केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। जब हस्तिनापुर के दूत संजय पांडवों तक संदेश लेकर आए कि "अपने सगे-संबंधियों को मारने से तो भीख मांगकर जीवित रहना ही बेहतर है," तब भगवान श्रीकृष्ण ने शांति दूत के रूप में कौरव सभा में जाकर कहा, "राज्य की रक्षा धर्म के मार्ग पर चलकर करनी चाहिए। दोनों पक्षों का कल्याण तभी संभव है जब न्याय और धर्म की रक्षा हो।"

लेकिन दुर्योधन ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्धभूमि की तैयारी के दौरान दोनों सेनाओं ने अपनी-अपनी छावनियां बनाई, रथ खड़े किए, द्वारपाल नियुक्त किए, और युद्ध के लिए पूरी व्यवस्था कर ली।

उस समय अर्जुन और श्रीकृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थित कराया। इसी जगह भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया।

भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्य बताने के साथ-साथ यह भी समझाया कि कर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "हे अर्जुन! मेरे लिए किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है, न तो मुझे किसी चीज़ की कमी है, फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अनासक्त भाव से कर्म करता है। तुम्हें भी यही करना चाहिए।"

अर्जुन के संदेह और मोहपाश को दूर करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उस दिव्य दृश्य में अर्जुन ने ईश्वर का सम्पूर्ण रूप देखा—जहां ब्रह्मांड की अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी सभी एक साथ सामंजस्य में दिखाई दे रही थीं। जीवन और मृत्यु, सृष्टि और विनाश—सब एक चक्र में प्रवाहित हो रहे थे। इस विराट दर्शन ने अर्जुन की अंतरात्मा को जागृत किया और उसे अपने कर्तव्य के मार्ग पर स्थिर किया।

गीता का उपदेश केवल युद्ध की पूर्व तैयारी का पाठ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में कर्म, योग और भक्ति के मार्ग का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि व्यक्ति अपने मन और आत्मा के विकास के लिए कर्म करें, समाज और मानवता के कल्याण के लिए प्रयास करें, और अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य का पालन करें। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को महसूस कर सकते हैं।

आज भी, जब हम गीता जयंती मनाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हर मानव के जीवन में कर्म, योग और भक्ति के मार्गदर्शन का प्रतीक है। मार्गशीर्ष अमावस्या को आरंभ हुए कुरुक्षेत्र युद्ध और उसी दिन दिया गया गीता उपदेश हमें यह संदेश देता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि कर्म, न्याय, ज्ञान और आत्म-साक्षात्कार में निहित है।

इस प्रकार गीता हमें जीवन का मार्गदर्शन देती है, जो न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज और मानवता के उत्थान में भी अनिवार्य है। अर्जुन की शंका और उसके संशय में दी गई श्रीकृष्ण की शिक्षाएं आज भी हर व्यक्ति के जीवन में सत्य और धर्म की खोज का मार्गदर्शन करती हैं। यही कारण है कि गीता का संदेश समय और स्थान की सीमाओं से परे है, और यह हर युग में मानव जीवन की दिशा निर्धारित करता रहेगा।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

गांधीनगर में सीएम फेलोशिप युवाओं की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

▸▸मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वरिष्ठ सचिवों के अनुभव और सीएम फेलोशिप में शामिल युवाओं के ज्ञान एवं कौशल के समन्वय से आम आदमी की सुख-सुविधा के साथ-साथ कारोबार सुगमता को और मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया

▸▸प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्रतिभाशाली युवाशक्ति के अभिनव विचारों के उपयोग के लिए 2009 में शुरू किया गया सीएम फेलोशिप प्रोग्राम सुशासन के लिए महत्वपूर्ण बना है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तनकारी बदलावों के जरिए आम आदमी की सुविधा और खुशहाली के कार्यों के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार सुगमता को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें इस संकल्प को युवाशक्ति के ज्ञान-कौशल और वरिष्ठ सचिवों के अनुभव के समन्वय से साकार करना है।

उन्होंने यह बात सीएम फेलोशिप के अंतर्गत चयनित एवं राज्य शासन में विविध विभागों में कार्यरत 24 सीएम फेलो की एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2009 में सीएम फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत करके प्रतिभाशाली युवाओं के अभिनव विचारों के साथ देश को सुशासन की एक नई राह दिखाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को, प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जनाभिमुख बनाकर टेक्नोलॉजी के उपयोग से जनहित के कार्यों के लिए पथप्रदर्शक करार दिया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरक वाक्य "हम सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि देश में बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ काम करते हैं" का भी उल्लेख किया।

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को चरितार्थ करने के लिए देश में अनेक बदलाव लाए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचाकर लोगों का जीवन अधिक आसान बनाया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 2009 में इस विचार के साथ कि 'दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ हो, वह गुजरात में भी हो' शुरू किया गया सीएम फेलोशिप कार्यक्रम, आज राज्य प्रशासन में प्रतिभाशाली युवाओं के योगदान का सर्वश्रेष्ठ मंच बन गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में इन व्यवस्थाओं के माध्यम से गुजरात को अग्रणी रखने के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

इस एक दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा) और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)-इंदौर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। स्पीपा के महानिदेशक श्री हरित शुक्ला और आईआईएम इंदौर के निदेशक श्री हिमांशु सिंह ने एमओयू का आदान-प्रदान किया। ये एमओयू विभिन्न 11 विषयों में लोक नीति प्रबंधन (पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट) के संदर्भ में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयुक्त आयोजन में उपयोगी साबित होगा।

मुख्य सचिव श्री एम.के. दास ने सीएम फेलोशिप के साथी युवाओं के योगदान तथा शोध एवं केस स्टडीज को सुशासन के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में सरदार पटेल गुड गवर्नेंस सीएम फेलोशिप को और गति मिली है।

इस एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया और राज्य सरकार के वरिष्ठ सचिवों ने सीएम फेलो युवाओं को मार्गदर्शन दिया। सीएम फेलो युवाओं ने इस अवसर पर अपने प्रेजेंटेशन दिए और बेस्ट प्रैक्टिसेज यानी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह और सचिव डॉ. विक्रांत पांडे सहित सीएम फेलो मौजूद रहे।

भारत पर्व-2025, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर : तेलंगाना की चेरियाल पेंटिंग ने मोहा आगंतुकों का मन

▸▸तेलंगाना की चेरियाल चित्रकार वंशिथा भारत पर्व मंच के जरिए देश की समृद्ध कला विरासत को उजागर कर रही हैं

▸▸24 वर्षीय वंशिथा चेरियाल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाती हैं पौराणिक कथाएं

▸▸तेलंगाना की चेरियाल पेंटिंग को मिला है जीआई टैग, कलाकार प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर हिंदू पौराणिक कथाओं का करते हैं वर्णन

24 वर्षीय कलाकार की चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत को उजागर कर रही है

तेलंगाना की 24 वर्षीय चेरियाल कलाकार सी.एच. वंशिथा और उनकी माता अपने राज्य की संस्कृति की सदियों पुरानी कहानियों को चेरियाल पेंटिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने और इस कला को संरक्षित करने के मिशन पर है। वे एकता नगर में भारत पर्व के माध्यम से इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। उल्लेखनीय है कि चेरियाल कला तेलंगाना के चेरियाल गांव की एक पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग शैली है। यह दृश्य कला के माध्यम से कहानी कहने की एक कला है। इसमें चित्रों का उपयोग पारंपरिक कहानी कहने के लिए किया जाता है। ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं, लोककथाओं और ग्रामीण जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। इस कला में जीवंत और जटिल कथात्मक चित्रों को खादी के कपड़े पर उकेरा जाता है। इसमें इमली के बीज के पेस्ट, चावल के स्टार्च और चाक पावडर के मिश्रण का उपयोग होता है, जो पेंटिंग के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।

(जीएनएस)। गांधीनगर : सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता नगर में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' परिसर में भारत सरकार और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 'भारत पर्व-2025' का भव्य आयोजन किया गया है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति, कला और हस्तकला को प्रदर्शित करने वाला यह जीवंत उत्सव अनेकता में एकता की झलक प्रस्तुत करता है। भारत पर्व में विभिन्न राज्यों की ओर से अपनी विशिष्ट विरासत का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिनमें तेलंगाना की अनोखी चेरियाल पेंटिंग को दर्शाने वाला स्टॉल अपने रंगों, कहानियों और इतिहास के लिए सबसे अलग नजर आ रहा है।

भारत पर्व : परंपरा, संदेश और रचनात्मकता का अनोखा समन्वय

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित भारत पर्व-2025 देश भर के कलाकारों और कारीगरों के लिए उनकी क्षेत्रीय परंपरा और धरोहर को प्रस्तुत करने का एक सशक्त मंच है। इस मंच के माध्यम से तेलंगाना की 24 वर्षीय युवती ने अपनी हस्तकला के जरिए भारत की 'विविधता में एकता' की भावना को प्रतिबिंबित किया है। डिजिटल आर्ट और मॉडर्न स्टोरीटेलिंग (कहानी कहने की कला) के इस युग में वंशिथा चेरियाल पेंटिंग जैसी कला की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।

मंत्रमुग्ध करने वाली तेलंगाना की चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग को मिला है जीआई टैग

तेलंगाना की चेरियाल पेंटिंग सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक सुंदर माध्यम है, जिसके रंग देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस कला को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिला है। चेरियाल पेंटिंग की विशेषता इसके प्राकृतिक रंग हैं। कलाकार पेंटिंग बनाने के लिए खनिज, फूल और समुद्री सीपियों आदि से प्राप्त रंगों का उपयोग करते हैं और उन्हें हस्तनिर्मित ब्रश के जरिए कपड़े पर उकेरते हैं। इस पेंटिंग में रामायण, महाभारत और स्थानीय लोक कथाओं जैसे भारतीय महाकाव्यों के दृश्यों को अद्भुत तरीके से चित्रित किया जाता है। प्रत्येक चित्र एक जीवंत दृश्य कहानी की तरह प्रकट होता है, जो ग्रामीण तेलंगाना की समृद्ध परंपराओं और जीवन शैली का वर्णन करता है। पृष्ठभूमि में चटक लाल रंग, चेहरे की अभिव्यक्ति और बोल्ड आउटलाइन चेरियाल पेंटिंग की पहचान हैं। पारंपरिक रूप से, लोक गायकों और कलाकारों द्वारा इन चित्रों का उपयोग अपनी कहानियां सुनाने के लिए किया जाता है, लेकिन आज इस हस्तकला का विस्तार वॉल हैंगिंग्स (फोटोफ्रेम या पोस्टर्स), मास्क और सजावटी कलाकृतियों की वस्तुओं तक हो गया है। इस हस्तकला को नक्काशी कलाकारों (चेरियाल चित्रकारों) की पीढ़ियां आगे बढ़ा रही हैं, जो सदियों पुरानी तकनीकों को संरक्षित रखते हुए उसमें नवाचार कर रहे हैं। भारत पर्व में बड़ी संख्या में आगंतुकों ने चेरियाल पेंटिंग को बड़ी उत्सुकता के साथ देखा और पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाले चित्रों का वर्णन भी सुना। पहली बार भारत पर्व जैसे कार्यक्रम में शामिल होने वाली और बी.टेक. की डिग्री हासिल कर चुकी सी.एच. वंशिथा ने कहा, "मैं बचपन से इस कला के साथ पली-बढ़ी हूं। मेरी माता पिछले 15 वर्षों से इस कला के प्रति समर्पित हैं और मैं गत चार वर्षों से इस कला से जुड़ी हुई हूं। हमारे द्वारा बनाए गए हरेक चित्र में हमारे देवताओं और पूर्वजों की कथाएं हैं। हमारा लक्ष्य इस कला के माध्यम से दुनिया को यह बताना है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है।"

दिव्यांगजनों के लिए नई नि:शुल्क सहायता सेवा

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल ने रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए एक नई निःशुल्क सहायता सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य रेल यात्रा को उनके लिए अधिक सहज, सुरक्षित और सुलभ बनाना है। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत आर आर केबल फाउंडेशन के सहयोग से यह महत्वपूर्ण पहल की गई है।

"सुगम्य भारत अभियान" के अंतर्गत वडोदरा मंडल के 66 स्टेशनों पर कुल 172 क्रचेस (86 जोड़ी) प्रदान किए गए हैं। ये क्रचेस रेलवे स्टेशनों पर सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग यात्रियों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह पहल न केवल दिव्यांगजनों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि रेलवे की सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोगी संस्थाओं के सकारात्मक योगदान को भी दर्शाती है। यह सेवा दिव्यांग यात्रियों के आत्मविश्वास और यात्रा अनुभव को और अधिक बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

अहमदाबाद मंडल के साणंद से पहली रेफ्रिजरेटेड कंटेनर रैक पिपावाव पोर्ट के लिए रवाना

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल के साणंद से दिनांक 17.11.2025 को M/s हस्ती पेट्रोकेमिकल्स एंड शिपिंग लिमिटेड की पहली रेफ्रिजरेटेड (रीफ़र) कंटेनर रैक (MHPL) (थार ड्राई पोर्ट) फ्रेट टर्मिनल साणंद से मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अहम पड़ाव मंडल के कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ बनाने तथा माल ढुलाई प्रणाली में दक्षता बढ़ाने के प्रति निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

यह रीफ़र कंटेनर रैक पिपावाव पोर्ट के लिए प्रस्थान कर रही है, जो क्षेत्र में बहु-मोडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी तथा तापमान-संवेदनशील माल की ढुलाई के लिए उद्योगों को एक विश्वसनीय और कुशल विकल्प प्रदान करेगी। यह पहल अहमदाबाद मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) की बढ़ती क्षमता और उद्योग जगत द्वारा मंडल की माल ढुलाई सेवाओं में जताए जा रहे विश्वास को दर्शाती है। इस रैक में जितने रेफ्रिजरेटेड कंटेनर लोड किए गए हैं, उनका कुल वजन 1061.81 टन है तथा इससे 6.57 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। इन कंटेनरों में M/s हाईफन इंडस्ट्रीज़, मैककेन इंडस्ट्रीज़ तथा बालाजी ग्रुप का नाजुक एवं शीघ्र नष्ट होने वाला माल शामिल है, जिसे समयबद्ध व नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है।

एमएचपीएल प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल से रीफ़र रैक संचालन की शुरुआत से क्षेत्र के निर्यातकों तथा कोल्ड-स्टोरेज आधारित उद्योगों को एक नई गति मिलेगी। यह अहमदाबाद मंडल की उद्योग विकास को समर्थन देने, माल सेवाओं का विस्तार करने तथा निर्बाध, सुरक्षित और कुशल लॉजिस्टिक्स प्रदान करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह उपलब्धि भारतीय रेल के अंतर्गत मंडल की सक्रिय पहल, नवाचार और सुदृढ़ फ्रेट इकोसिस्टम निर्माण के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभरती है।

अहमदाबाद मण्डल पर भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस का उत्साहपूर्वक आयोजन

(जीएनएस)। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर अहमदाबाद मंडल में जनजातीय गौरव दिवस बड़े हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात उनके जीवन-वृत, संघर्ष तथा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला गया।

अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि "भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में वह कार्य कर दिखाया, जो बड़े-बड़े लोग भी नहीं कर पाते। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष कर आदिवासी समाज को

एकजुट किया और समाज सुधार एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए विशिष्ट योगदान दिया।" उन्होंने आगे कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और देशभक्ति का प्रेरणास्रोत है, जो वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस अवसर पर वक्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तथा आदिवासी समाज के उत्थान हेतु किए गए उनके उल्लेखनीय कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित पुस्तिका का वितरण भी किया गया।

कार्यक्रम में मण्डल के रेल अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न एसोसिएशनों एवं ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय कमज़ोरी के कारण अक्टूबर में निर्यात में गिरावट भारत का व्यापार घाटा बढ़ा: फियो अध्यक्ष, एस सी रल्हन

(जीएनएस)। फियो अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन ने अक्टूबर के व्यापार आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नवीनतम आंकड़े मिश्रित रुझान दर्शाते हैं, जिसमें कुल निर्यात में मामूली गिरावट और आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ़ा है। अक्टूबर 2025 में भारत का कुल निर्यात 72.89 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो अक्टूबर 2024 में दर्ज 73.39 अरब अमेरिकी डॉलर से थोड़ा कम है। हालाँकि, आयात पिछले वर्ष के 82.44 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 94.70 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे इस महीने कुल व्यापार घाटा 21.80 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

श्री रल्हन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यापारिक निर्यात में गिरावट—जो एक वर्ष पहले अक्टूबर 2025 में 38.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 34.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई—मुख्य रूप से कई प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में तीव्र गिरावट के कारण हुई। इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, परिधान एवं वस्त्र, जैविक एवं अकार्बनिक रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक के सामान जैसे प्रमुख सेक्टरों में उल्लेखनीय दबाव देखा गया, जिससे समग्र निर्यात प्रदर्शन प्रभावित हुआ। इस बीच, व्यापारिक आयात अक्टूबर 2024 के 65.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में बढ़कर 76.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे व्यापारिक व्यापार घाटा 41.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

फियो प्रमुख ने कहा कि निर्यात में यह दबाव व्यापक वैश्विक आर्थिक मंदी को दर्शाता है, जो भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, कई प्रमुख बाजारों में कम माँग और वस्तुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव से चिह्नित है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय निर्यातकों ने लचीलापन दिखाया है, जबकि बढ़ी हुई लॉजिस्टिक्स लागत और उतार-चढ़ाव वाली इनपुट कीमतें प्रतिस्पर्धात्मकता को चुनौती दे रही हैं।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आयात में वृद्धि—विशेषकर महत्वपूर्ण इनपुट और घटकों की—भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की आयातित कच्चे माल पर निरंतर निर्भरता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, समय पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के प्रयासों में तेजी लाना प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने रहने चाहिए।

अप्रैल-अक्टूबर 2025 के लिए क्षेत्रीय प्रदर्शन रुझानों पर प्रकाश डालते हुए, श्री रल्हन ने बताया कि भारत की शीर्ष 10 निर्यात वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा उत्पादों सहित सूती धागे/कपड़े/मेड-अप, चावल और प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद शामिल हैं।

यात के संदर्भ में, इसी अवधि के दौरान शीर्ष 10 वस्तुओं में पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, मशीनरी और विद्युत उत्पाद, परिवहन उपकरण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, अलौह धातुएँ, कोयला और संबंधित उत्पाद, प्लास्टिक सामग्री, और लोहा एवं इस्पात शामिल थे।

बढ़ते व्यापार अंतर पर चिंता व्यक्त करते हुए, श्री रल्हन ने निर्णायक और समय पर नीतिगत हस्तक्षेप का आग्रह किया। उन्होंने निर्यात समर्थन उपायों को बढ़ाने, विभिन्न योजनाओं के तहत लाभों को शीघ्र जारी करने, बेहतर और किफायती ऋण पहुँच और अनुपालन बोझ को कम करने की आवश्यकता दोहराई ताकि निर्यातक चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में प्रतिस्पर्धी बने रह सकें। श्री रल्हन ने निर्यात संवर्धन मिशन और निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा निरंतर समर्थन के लिए, साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय पर व्यापार संबंधी राहत उपायों के लिए भी आभार व्यक्त किया, जिनमें निर्यात प्राप्ति अवधि का विस्तार, अग्रिम भुगतान निर्यात के लिए शिपमेंट की समय-सीमा में वृद्धि, प्रभावित सेक्टरों के लिए ऋण चुकौती में राहत और निर्यात ऋण चुकौती में छूट शामिल हैं। हालाँकि, उन्होंने रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया कि वह पारस्परिक शुल्क से प्रभावित सभी निर्यातकों को राहत प्रदान करे, न कि केवल विशिष्ट सेक्टरों तक सीमित रखे।

फियो को उम्मीद है कि निरंतर नीतिगत समर्थन और वैश्विक माँग स्थितियों में क्रमिक सुधार के साथ, भारत का निर्यात क्षेत्र आने वाले महीनों में मजबूती से उबरने की स्थिति में है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद के घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र में 'सरदार@150 यूनिटी मार्च' आयोजित

▸▸मुख्यमंत्री ने यूनिटी मार्च-पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

▸▸भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा, प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल और राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला सहित कई गणमान्य लोगों की विशेष उपस्थिति

▸▸स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की सामूहिक शपथ ली गई

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▸▸सरदार साहब की 150वीं जयंती पर 'एकता मंत्र' को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विधानसभा क्षेत्रवार यूनिटी मार्च का आयोजन

▸▸प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर भारत को एक और अखंड बनाया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक और आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल के 150वें जयंती समारोह के अंतर्गत घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र की 'सरदार@150 यूनिटी मार्च' पदयात्रा को सोमवार को अहमदाबाद के आंबली इलाके से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन-जन में राष्ट्रीय एकता का भाव उजागर करने के लिए यूनिटी मार्च आयोजित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने 9 नवंबर को जूनागढ़ से इस राज्यव्यापी यूनिटी मार्च का शुभारंभ करने के बाद, विधानसभा क्षेत्रवार इस मार्च के आयोजन के तहत सोमवार सुबह अपने घाटलोडिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 562 रियासतों का एकीकरण कर एक और अखंड भारत का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एकता के उसी मंत्र को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' से साकार किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर कटक से कच्छ और कश्मीर से कन्याकुमार तक एक भारत बनाया है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के निर्माण के जरिए सरदार पटेल को सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि दी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यह प्रतिमा भारत के सामर्थ्य और गौरवशाली इतिहास का श्रेष्ठ प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में विकास की राजनीति स्थापित की है, उनके नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' मंत्र के माध्यम से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी सरदार साहब को याद करके और स्वदेशी को जीवन का एक हिस्सा बनाकर विकसित भारत का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि हम सभी एक और नेक बनकर 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए कटिबद्ध बनें।

इस यूनिटी मार्च में शामिल सभी लोगों ने स्वदेशी को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान देने की सामूहिक शपथ ली।

अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन ने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित यूनिटी मार्च सरदार पटेल को सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा, प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा और श्री नरहरिभाई अमीन, महानगर प्रभारी श्री रजनीभाई पटेल, शहर के विधायक, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन श्रीमती धर्मिष्ठाबेन गज्जर, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, शहर पुलिस आयुक्त श्री जी.एस. मलिक, जिला कलेक्टर श्री सुजीत कुमार, जिला विकास अधिकारी श्री विदेह खरे, कई साधु-संत, पूर्व राज परिवारों के सदस्य, पार्षदगण, पार्टी के पदाधिकारी, युवाओं और विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

दिल्ली धमाके की चौंकाने वाली सच्चाई: दिन में डॉक्टर, रात में 'वुल्फ पैक' की सरगना शाहीन सईद का पाकिस्तानी आतंक जाल उजागर

(जीएनएस)। दिल्ली धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने आतंक की एक ऐसी भयावह तस्वीर उभरकर आई है, जिसने अनुभवी जांचकर्ताओं तक के होश उड़ा दिए हैं। यह कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं, बल्कि उस गहरे और संगठित नेटवर्क की है जिसे सीमा पार से संचालित किया जाता था और जिसकी कमान एक पढ़ी-लिखी, मासूम चेहरे वाली, पर भीतर से खतरनाक साजिशों की माहिर खिलाड़ी—डॉ. शाहीन सईद—के हाथों में थी। दिन में सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करने वाली यह महिला रात ढलते ही आतंक की दुनिया की 'मैडम सर्जन' बन जाती थी।

दिल्ली धमाके के बाद जब जांच एजेंसियों ने संदिग्ध डिजिटल डाटा, चैट बॉक्स और कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, तो उन्हें सबसे पहले एक अनोखा शब्द दिखा—WOLF PACK। यह कोई साधारण ग्रुप नहीं था, बल्कि वह डिजिटल तहखाना था, जहां रात के सन्नाटे में भारत को दहलाने की योजनाएं बनाई जाती थीं। इस ग्रुप का संचालन किसी प्रशिक्षित आतंकी के नहीं, बल्कि उसी मैडम सर्जन के हाथों में था, जिसे भारत में एक डॉक्टर के रूप में जाना जाता था। यह वुल्फ पैक का पूरा खेल 'वुल्फ आवर' यानी रात 11 बजे से 2 बजे के बीच चलता था। दुनिया जब नींद में होती थी, तब इस ग्रुप के सदस्य एक्टिव होते थे। चैट में 'HOWL' जैसे कोड वर्ड से बातचीत की शुरुआत होती और फिर शुरू होता आतंक का काला खेल। इस कोड के पीछे पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं की योजना थी—एक ऐसी योजना जिसमें महिला ब्रिगेड का इस्तेमाल कर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को नए तरीके से निशाना बनाया जा सके।

जांच के दौरान यह स्पष्ट होता गया कि शाहीन सईद सीमा पार से संचालित 'जमात-उल-मोमिनात' की भारत प्रभारी बन चुकी थी। मसूद अजहर की बहन सादिया और उसके भतीजे उमर फारूख की पत्नी अफीरा बीबी उससे सीधे संपर्क में थीं। वही अफीरा, जिसका पति पुलवामा हमले में शामिल था और बाद में मारा गया था। महिलाओं को कट्टर

बनाना, ब्रेनवॉश करना और भेड़ियों की तरह संगठित कर दो टीमों—ऑरोरा और लूना—में बांटना, यह सब शाहीन की ही जिम्मेदारी थी।

सबसे हैरान करने वाला तथ्य यह था कि शाहीन सिर्फ नेटवर्क तैयार नहीं कर रही थी, बल्कि खुद भी इस आतंकी मॉड्यूल का सक्रिय हिस्सा थी। उसकी गतिविधियों को देखकर जांच एजेंसियों को शक है कि वह साल 2016 से 2018 के बीच UAE में नौकरी के दौरान पाकिस्तान भी गई थी, जहां उसे बाकायदा आतंकी ट्रेनिंग मिली। इससे पहले वह 2013 में नौकरी से गायब हुई और करीब आठ साल तक अंडरग्राउंड रही।

मुनीर, जो इस वक्त पाकिस्तान की पूरी आतंक मशीनरी को संचालित कर रहा है, ने शाहीन और उसके नेटवर्क को भारत के खिलाफ खुली छूट दे दी थी। दिल्ली धमाके में दूर बैठकर रिमोट ऑपरेटेड निर्देश इसी मुनीर के नेटवर्क से भेजे गए थे। चैटबॉक्स के कई संदेश ऐसे हैं जिनमें सीधे-सीधे पाकिस्तान में बैठे आकाओं के आदेश दर्ज हैं।

दिल्ली धमाके का 'वुल्फ कोड' सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि इस पूरे आतंक नेटवर्क का वह अंधेरा सच है, जिसमें महिलाएं भी उतनी ही क्रूरता से शामिल थीं जितना प्रशिक्षित आतंकी। शाहीन किसी सामान्य आतंकी से कहीं ज्यादा खतरनाक थी—क्योंकि उसके पास दिमाग था, शिक्षा थी, और अपने दोहरे चेहरे को छिपाने की क्षमता भी।

इस खुलासे के बाद सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दिल्ली धमाके की साजिश किसने रची, बल्कि यह कि पाकिस्तान किस हद तक जाकर भारत में आतंक फैलाने के लिए नई रणनीतियां तैयार कर रहा है।

और यह भी कि आतंकी नेटवर्क अब महिलाओं को हथियार बनाकर कैसे एक नया, अदृश्य मोर्चा खड़ा कर रहा है।

दिल्ली धमाके की जांच ने इस बात को साफ कर दिया है कि आतंकवाद का चेहरा बदल चुका है। अब यह सिर्फ बंदूक और बारूद तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल समूहों, कोडेड संदेशों, व्हाट्सऐप ग्रुपों और दुश्मन देशों से नियंत्रित स्लीपर सेल के रूप में हमारे सामने है।

मैडम सर्जन और उसका 'वुल्फ पैक' भारत को एक नए तरीके से चुनौती दे रहा था—लेकिन अब उसका भंडाफोड़ हो चुका है।

और यह साफ हो गया है कि आतंक का हर नया रूप जितना खतरनाक है, उतना ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती भी है लेकिन वह तैयार भी हैं।

मुंबई–ठाणे में गैस संकट ने रोकी शहर की रफ्तार, मुख्य पाइपलाइन टूटने से CNG सप्लाई ठप, घंटों लाइन में खड़े रहे ड्राइवर

(जीएनएस)। मुंबई और ठाणे जैसे महानगरों की रफ्तार सोमवार को अचानक थम-सी गई, जब सीएनजी की सप्लाई बड़ी मात्रा में बाधित हो गई। शहर के बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बड़ा हिस्सा जिस ईंधन पर चलता है, उसकी आपूर्ति रुकते ही पूरा तंत्र अस्त-व्यस्त हो उठा। महानगर गैस लिमिटेड ने साफ किया कि यह संकट किसी तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम नहीं, बल्कि GAIL की मुख्य गैस पाइपलाइन को हुए बड़े नुकसान की वजह से पैदा हुआ है। यह पाइपलाइन RCF परिसर के भीतर क्षतिग्रस्त हुई, जिससे वडाला स्थित MGL सिटी गेट स्टेशन पर सप्लाई अचानक रुक गई और मिनटों में पूरा नेटवर्क प्रभावित हो गया।

जैसे ही गैस का दबाव कम होना शुरू हुआ, मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के कई सीएनजी पंप एक-एक कर बंद होने लगे। यह बंदी सिर्फ निजी वाहनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन पंपों को भी प्रभावित कर गई, जहां से प्रतिदिन हजारों बसों और ऑटो-रिक्शों को ईंधन मिलता है। सड़कें खाली दिखने लगीं,

टैक्सियों और ऑटो के स्टैंड सूने पड़े और जहां पंप थोड़े बहुत खुले रहे, वहां लंबी-लंबी कतारों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई ड्राइवरों की शिकायत थी कि वे दो से तीन घंटे लाइन में खड़े रहने के बावजूद गैस नहीं भरवा सके और पंप बंद कर दिए गए।

मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह सीएनजी पर आधारित है। बेस्ट बसों से लेकर लोकल कनेक्टिविटी देने वाले ऑटो और टैक्सी — सबकी निर्भरता इसी ईंधन पर है। ऐसे में सप्लाई बंद होते ही हजारों यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ीं। सुबह-शाम दफ्तर के समय वाहनों की भारी कमी महसूस की गई और कई रूटों पर बस सेवाएं भी प्रभावित रहीं। कुछ निजी टैक्सी यूनियनों ने बताया कि सप्लाई बंद रहने से उन्हें सेवाएं बंद करनी पड़ीं, जिससे दैनिक आय पर सीधा असर पड़ा।

इस बीच MGL ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि घरेलू पाइप्ड गैस की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध गैस पहले आवासीय क्षेत्रों में भेजी जा रही है ताकि रसोई गैस की आवश्यक जरूरतें पूरी होती रहें। वहीं, कमर्शियल उपभोक्ताओं — जैसे होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक यूनिट्स — को अस्थायी रूप से वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। गैस पाइपलाइन को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए GAIL और MGL की संयुक्त तकनीकी टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर काम शुरू किया। विशेषज्ञों का कहना है कि पाइपलाइन को हुए नुकसान की मरम्मत में कई घंटे लग सकते हैं, और जब तक वडाला CGS पर सप्लाई पूरी क्षमता में बहाल नहीं होती, तब तक शहर की सीएनजी व्यवस्था सामान्य नहीं हो पाएगी। MGL ने उम्मीद जताई है कि दबाव स्थिर होते ही पूरे नेटवर्क में सप्लाई फिर से सुचारु हो जाएगी।

कंपनी ने शहरवासियों और वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि देश की आर्थिक राजधानी का एक बड़ा हिस्सा अब भी एक ही ईंधन स्रोत पर कितना निर्भर है और किसी भी तकनीकी झटके से शहर की रफ्तार पल भर में रुक सकती है।

सीकर की हवेली में मिली 125 साल पुरानी रहस्यमयी तिजोरी ने बढ़ाई हलचल, खज़ाने की अटकलों से गांव में उत्साह और तनाव दोनों चरम पर

(जीएनएस)। राजस्थान के सीकर जिले के हसामपुर गांव में एक 125 साल पुरानी हवेली के निर्माण कार्य के दौरान अचानक जमीन के नीचे दबा इतिहास सामने आ गया। मजदूरों ने खोदाई करते समय जो लोहे की विशाल और बेहद भारी तिजोरी निकलती देखी, उसने पूरे गांव को चौंका दिया। सुबह की यह खोज दोपहर तक गांव की मुख्य चर्चा बन गई और शाम तक यह रहस्य पूरे इलाके में फैल चुका था कि आखिर इस पुरानी हवेली की तिजोरी में क्या दबा हो सकता है। हवेली कभी गांव के प्रसिद्ध मुसद्दीलाल तिवारी परिवार की थी। समय बीतने के साथ यह परिवार गांव छोड़कर ओडिशा और दिल्ली में बस गया और हवेली कई खरीददारों के हाथों से गुजरते हुए आज अपने नए मालिकों के पास है। वर्तमान में यहीं निर्माण कार्य चल रहा था, जब यह लोहे की तिजोरी करीब डेढ़ फीट नीचे दबे स्वरूप में दिखाई दी। तिजोरी का आकार बड़ा है, वजन इतना कि दो-तीन लोग मिलकर भी उसे उठाने में मुश्किल

महसूस कर रहे थे। इसके बाहर आते ही मजदूरों ने मालिक को सूचना दी और देखते ही देखते गांव के लोग वहां उमड़ पड़े।

लोगों की कल्पनाएं भी उसी गति से दौड़ने लगीं जिस गति से भीड़ वहां एकत्रित हो रही थी। किसी ने कहा कि इसमें सोने-चांदी के पुराने जेवर होंगे, किसी ने तिवारी परिवार के प्राचीन दस्तावेज होने की आशंका जताई। कुछ बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा कि यह तिजोरी संभवतः तिवारी परिवार द्वारा वर्षों पहले संचित खजाने को सुरक्षित रखने के लिए दफन की गई होगी। कुछ लोग मुगलकालीन सिक्कों या दुर्लभ धातुओं के होने की संभावना भी बताने लगे। गांव की चर्चा में रोमांच और रहस्य का एक ऐसा मिश्रण था जिसने लोगों में हलचल पैदा कर दी।

भीड़ बढ़ते देख किसी ने पुलिस को सूचना दी। पाटन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। तिजोरी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया गया ताकि कोई नुकसान न हो और न ही कोई विवाद पैदा हो। थानाधिकारी रमेश मीणा ने तिजोरी को कब्जे में लेकर सील किया और उसे पुलिस सुरक्षा के बीच पाटन थाने पहुंचाया गया। तिजोरी किस तकनीक से बनी है, कितनी पुरानी है और किस तरह से खोली जा सकती है—इसका निरीक्षण पुलिस और प्रशासनिक टीमें कर रही हैं।

पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि तिजोरी को जल्दबाज़ी में नहीं खोला जाएगा। यह तभी खोली जाएगी जब दो पक्ष—तिवारी परिवार, जो हवेली के मूल मालिक थे, और वर्तमान के खरीदार—दोनों मौजूद हों और उनकी सहमति से पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और पंचनामा तैयार किया जा सके। यह कदम इसलिए ताकि जो भी सामग्री निकले, उसके स्वामित्व को लेकर बाद में कोई विवाद पैदा न हो और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो।

हसामपुर गांव अब पूरी तरह इस रहस्यमयी तिजोरी की कहानी में डूबा हुआ है। खेतों से लेकर चौपालों तक बस एक ही चर्चा है कि आखिर तिजोरी में क्या छिपा होगा—पुराना खज़ाना, दस्तावेज, या फिर कोई ऐतिहासिक धरोहर? तिजोरी अभी पुलिस थाने में सील बंद है, लेकिन गांव का रोमांच अपने चरम पर है। लोग सिर्फ एक दिन का इंतज़ार कर रहे हैं—जिस दिन तिजोरी खुलेगी और सौ साल से ज्यादा पुराने रहस्य से पर्दा उठेगा।

राजभवन में हथियारों की अफवाह से बंगाल की सियासत में भूचाल, राज्यपाल बनाम टीएमसी संघर्ष नई कगार पर

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर तूफ़ान की लपटों में घिर गई है, जहां पहले भी राजभवन और राज्य सरकार के बीच तनातनी कई बार सुर्खियाँ बन चुकी है, मगर इस बार हालात और भी गंभीर हो गए हैं। एक साधारण राजनीतिक टिप्पणी ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी, जिसके केंद्र में खुद राज्यपाल सीवी आनंद बोस और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी आमने-सामने आ गए हैं।

यह सब शुरू हुआ कल्याण बनर्जी के उस बयान से जिसने राजनीतिक तापमान को अचानक कई डिग्री बढ़ा दिया। उन्होंने सार्वजनिक मंच से दावा किया कि पश्चिम बंगाल का राजभवन हथियारों और गोला-बारूद का गोदाम बन चुका है, जहां राजनीतिक अपराधियों को बुलाकर बम और बंदूकें बाँटी जाती हैं। इस आरोप ने राज्य की राजनीति में अचानक आग लगा दी। बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में राजभवन पर इस तरह की बात कहना एक बड़े तूफ़ान की शुरुआत थी, और वही हुआ।

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इसे सीधे अपने संवैधानिक पद की मर्यादा पर हमला माना। आरोप लगते ही सोमवार सुबह उन्होंने किसी भी तरह की देरी किए बिना राजभवन में कोलकाता पुलिस, राजभवन पुलिस, सीआरपीएफ, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को बुलाकर पूरे परिसर की विस्तृत तलाशी करवाने का आदेश दिया। यह नज़ारा ऐसा था जो शायद बंगाल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया—एक तरफ भारी सुरक्षा बल, दूसरी तरफ राज्यपाल के निर्देश पर हर कमरे, हर कॉरिडोर और हर दीवार की बारीकी से जाँच।

तलाशी पूरी होने के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तो राज्यपाल का रुख और सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोपों की सच्चाई उजागर करना उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर आरोप झूठे साबित हुए तो कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य होगी। उन्होंने साफ़ कहा कि अब बंगाल में राज्यपाल पर बेबुनियाद आरोप लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए और कल्याण बनर्जी को इस टिप्पणी की क़ीमत चुकानी पड़ सकती है।

राज्यपाल से जब पूछा गया कि क्या इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कूटनीतिक जवाब देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों के बीच होने वाली बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि सही समय आने पर राजभवन तथ्यों को सार्वजनिक करेगा।

नकली नोटों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बेनक़ाब: YouTube से सीखी तकनीक, तीन जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ रेड में बड़ा खुलासा

(जीएनएस)। मध्य प्रदेश में नकली करेंसी का एक संगठित और चौंकाने वाला नेटवर्क सक्रिय था, जिसकी जड़ें भोपाल, खंडवा और रतलाम तक फैली हुई थीं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने इस गिरोह के राज़ खोल दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड कोई हाईटेक अपराधी नहीं, बल्कि सिर्फ 10वीं पास एक युवक निकला, जिसने यूट्यूब वीडियो देखकर नकली नोट छापने की पूरी तकनीक सीख ली थी। उसकी यह 'घर बैठे नकली करेंसी फैक्ट्री' पिछले एक साल से चल रही थी और छह लाख रुपये से अधिक के नकली नोट बाजार में खपाए जा चुके थे। भोपाल पुलिस को सूचना मिली कि पिपलानी इलाके के शांति नगर में रहने वाला विवेक यादव अपने कमरे में प्रिंटर और स्कैनर की मदद से 500-500 रुपये के नकली नोट छाप रहा है। छापेमारी में करीब दो लाख रुपये से अधिक के तैयार नकली नोट, आधे तैयार नोट, रंग-कागज और प्रिंटिंग उपकरण जब्त किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले 10 साल तक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था और उसी

जानकारी के आधार पर जर्मन प्रिंटिंग तकनीक से जुड़े वीडियो देखकर नकली नोट बनाने का तरीका सीख लिया। वह छोटी दुकानों पर 20-50 रुपये की चीज खरीदकर बदले में असली नोट ले लेता था। बार-बार छोटी रकम में ट्रांजैक्शन करने पर किसी को शक नहीं हुआ और इस चतुराई से उसने करीब 6 लाख रुपये की नकली करेंसी बाजार में चला दी थी।

दुकानदारों की सतर्कता ने आरोपी की करतूत पकड़ी। जब कुछ दुकानदारों को नोट पर संदेह हुआ और उन्होंने सवाल उठाए, तो आरोपी ने उन्हें लालच देते हुए कहा कि एक लाख रुपये देगा, बस शिकायत न करें। इसी बातचीत में दुकानदारों ने उसका वीडियो बना लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र के अनुसार, आरोपी का किसी बड़े नेटवर्क से संबंध है या वह खुद किसी संगठन को नकली नोट सप्लाई करता था, इसकी जांच जारी है।

इधर खंडवा में पुलिस ने एक मदरसे पर छापा मारा, जहां से लगभग 19 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए। यहां नोट बड़ी मात्रा में छापे जाते थे और फिर अलग-अलग राज्यों में सप्लाई किए जाते थे। मौके से हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग सामग्री, कागज और बड़ी संख्या में अधूरे नोट जब्त हुए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और कई राज्यों में इसकी जड़ें हो सकती हैं।

रतलाम में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया जो ट्रेन और बस स्टैंड इलाके में नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से बड़ी संख्या में 200 और 500 के नकली नोट मिले। पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों भी किसी बाहरी रैकेट के संपर्क में थे और बाजार में खपाने से ठीक पहले गिरफ्तार किए गए।

तीनों जिलों की कार्रवाई ने पुलिस को इस बात के संकेत दिए हैं कि नकली नोटों का यह नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस पूरे मामले की गहराई को देखते हुए जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंपने की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार राष्ट्रीय और संभवतः अंतरराज्यीय स्तर तक जुड़े हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इससे भी बड़े खुलासे होने और ताकतवर नेटवर्क बेनक़ाब होने की संभावना है।

इधर कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है और गृह विभाग पूरी तरह फेल है। उनका कहना है कि प्रदेश में लगातार नकली करेंसी की बरामदगी इस बात का सबूत है कि अपराधी बेखौफ होकर गिरोह चला रहे हैं।

पुलिस की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि नकली नोटों का यह खेल सिर्फ तकनीकी ज्ञान और डिजिटल संसाधनों के दम पर कितनी तेजी से फैल रहा था और कैसे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से सीखकर भी अपराध की एक बड़ी चेन खड़ी की जा सकती है। जांच आगे बढ़ते ही इस नेटवर्क की और परतें खुलने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में फैले ऐसे रैकेटों पर भी कार्रवाई की ज़मीन तैयार होगी।

"रोहिणी के सम्मान पर तेज प्रताप का बड़ा बयान: 'परिवार पर वार करने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा'"

(जीएनएस)। बिहार की राजनीति इन दिनों सिर्फ चुनावी नतीजों की वजह से नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर उठी तीखी हलचलों के कारण भी चर्चा के केंद्र में है। चुनावी पराजय के बाद आरजेडी में उभरा आंतरिक तनाव धीरे-धीरे सार्वजनिक विवाद में बदल रहा है। इसी क्रम में शनिवार को लालू यादव की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक राजनीति से दूरी बनाने और परिवार से भी अलग होने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। यह बात न सिर्फ राजद समर्थकों के लिए बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल के लिए अप्रत्याशित थी।

रोहिणी के इस बयान ने पार्टी और परिवार, दोनों में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर उनका संदेश भावनाओं से भरा था—एक ऐसी पीड़ा और असंतोष की आवाज जिसे वे अब तक भीतर ही भीतर दबाए थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नाराज़गी सार्वजनिक की, सबसे पहले और सबसे तीखी प्रतिक्रिया उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ओर से सामने आई।

तेज प्रताप, जो अक्सर अपनी बेबाक और

उग्र शैली से सुर्खियों में रहते हैं, इस बार भी अपनी बहन के सम्मान के सवाल पर आग की तरह भड़क उठे। शनिवार को दिए अपने पहले बयान में उन्होंने चेतावनी के स्वर में लिखा था कि जो भी उनकी बहन का अपमान करेगा, उस पर "कृष्ण का सुदर्शन चक्र" चलेगा। उनका यह बयान न सिर्फ राजनीतिक था, बल्कि भावनात्मक भी—एक भाई की अपनी बहन के लिए सुरक्षा और सम्मान की दृढ़ घोषणा।

लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। सोमवार को तेज प्रताप ने एक और बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया कि यह मामला केवल राजनीति का नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान का है। उन्होंने एक्स पर लिखा—

"हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा।"

तेज प्रताप का यह संदेश भीतर जमा हुए गुस्से और परिवार के प्रति उनके अटूट समर्पण की झलक माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ पहले जो कुछ हुआ, उसे वे चुपचाप सह गए, लेकिन रोहिणी के साथ हुआ अपमान असहनीय है। उनके शब्दों में पीड़ा भी थी और चेतावनी भी। उन्होंने आगे लिखा—"रोहिणी दीदी जो बात कह रही हैं, वह बिल्कुल सही है। एक मां, एक महिला और एक बहन होने के नाते उन्होंने जो साहस दिखाया है, वह इतिहास बनेगा। उनकी भावनाएँ सुनहरे अक्षरों में दर्ज होंगी।" राजनीतिक गलियारों में इस पूरे विवाद को लालू परिवार के भीतर बढ़ रही दरार का संकेत माना जा रहा है। सूत्रों की मानें तो चुनावी रणनीति, टिकट वितरण और कुछ नेताओं की कथित लामबंदी ने विवाद को जन्म दिया है। रोहिणी लंबे समय से बिहार राजनीति में सक्रिय समर्थन की भूमिका निभाती रही हैं—चाहे वह सोशल मीडिया पर पार्टी का बचाव हो या परिवार की छवि को मजबूत करना। ऐसे में उनका राजनीति और परिवार से दूरी बनाने का एलान बड़े झटके के रूप में लिया जा रहा है।

तेज प्रताप के बयान से यह संकेत साफ है कि वे बहन के सम्मान के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की सुलह-सफ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। 'जयचंद' शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जानबूझकर किया है—यह उन लोगों की ओर इशारा है जिन्हें वे रोहिणी के खिलाफ हुए दुर्व्यवहार का जिम्मेदार मानते हैं। यह संकेत परिवार या पार्टी के भीतर ही कुछ नेताओं की तरफ माना जा रहा है, हालांकि तेज प्रताप ने किसी का नाम नहीं लिया।

आरजेडी समर्थक इस विवाद से उलझन में हैं। पार्टी पहले ही चुनावी हार के बाद मुश्किल दौर से गुजर रही है, और अब परिवार का यह आंतरिक संकट संगठन के मनोबल पर असर डाल सकता है। कई वरिष्ठ नेता पर्दे के पीछे तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन तेज प्रताप के सार्वजनिक रुख ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है।

इस बीच रोहिणी आचार्य फिलहाल चुप हैं, लेकिन उनके बयान ने इतना साफ कर दिया है कि उनकी पीड़ा गहरी है।

तेज प्रताप का समर्थन उन्हें शक्ति दे सकता है, लेकिन लालू परिवार को एकजुट रखना अब पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है।

बिहार की राजनीति में यह प्रकरण लंबे समय तक चर्चा का विषय रहेगा—क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ चुनावी हार-जीत का नहीं, बल्कि उस परिवार के भीतर की दरारों का है जिसने दशकों तक राज्य की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखा।

सुरों में झूम उठा झारखंड—सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने मंच पर गाया सुपरहिट बॉलीवुड गीत, मोरहाबादी मैदान बना तालियों का समंदर

(जीएनएस)। झारखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव इस बार सिर्फ आतिशबाज़ी, रोशनी और सरकारी आयोजनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और यादगार शाम में बदल गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में हजारों लोग उमड़ पड़े थे, राज्य निर्माण की रजत वर्षगांठ का साक्षी बनने के लिए। मौसम में हल्की ठंडक थी, लेकिन मैदान में मौजूद हजारों दिलों में उत्साह की गर्मी थी—और ठीक इसी माहौल में वह क्षण आया जिसने पूरे झारखंड को चौंका भी दिया और गर्व से भर भी दिया।

जब बॉलीवुड की जानी-मानी प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव मंच पर अपनी मधुर आवाज़ से संगीत की बारिश कर रही थीं, तब दर्शकों के बीच से अचानक एक हलचल हुई। एक परिचित चेहरा भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था—राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और खुद एक जनप्रतिनिधि, कल्पना सोरेन। उस क्षण किसी ने नहीं सोचा था कि वे सीधे मंच पर चढ़ने वाली हैं। लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए मंच संभाला और शिल्पा राव के साथ सुरों की

वह साझेदारी की, जिसे देखने के लिए शायद अगली कई सालों तक लोग किस्से सुनाते रहेंगे।

मंच पर खड़ी कल्पना सोरेन ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म का लोकप्रिय गीत गुनगुनाया। मैदान में मौजूद भीड़ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक तालियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की निगाहें मंच पर टिकी थीं, जहां झारखंड की बहू और नेतृत्त्व की पहचान रखने वाली कल्पना सोरेन एक कलाकार की तरह खड़ी थीं—पूरी तन्मयता, पूरी ऊर्जा और पूरे आत्मविश्वास के साथ।

शिल्पा राव साथ में मुस्कुरा रही थीं, संगीतकार ताल पर थिरक रहे थे, और दर्शक अपनी मोबाइल फ्लैश लाइट्स जलाकर इस क्षण को अमर कर रहे थे।

सोशल मीडिया भी इस दृश्य का उतना ही दीवाना हो उठा। कल्पना सोरेन ने एक्स पर मंच से अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा—

"बॉलीवुड की मशहूर गायिका और झारखंड की बेटी शिल्पा राव ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से रजत वर्ष उत्सव को यादगार बना दिया।"

एक और तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा—"झारखंड की बेटी, मशहूर सिंगर और नेशनल अवॉर्ड विजेता शिल्पा राव के साथ मंच पर एक छोटी सी कोशिश।"

इस छोटी-सी कोशिश का असर छोटा नहीं था। झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दोनों की मौजूदगी ने इस सरकारी समारोह को एक परिवारिक और भावनात्मक रूप दे दिया। लोग कहने लगे—यह सिर्फ राज्य का जन्मदिन नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा का उत्सव है।